

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : सुशिल कुमार सैनी (आर.ए.एम्.)

राजस्व वाद संख्या 64/2024

लक्ष्मणसिंह

बनाम

किशन कंवर आदि

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा।

प्रार्थना पत्र - अं.आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

व धारा 151 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट वादी अप्रार्थी - श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत
ऐडवोकेट प्रति० प्रार्थी - श्री राजीव सिंह शेखावत

:: आदेश ::

दिनांक 23.12.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :- ग्राम बागोरियां की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1637, 1575 में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजीयात के संबंध में वादी द्वारा एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में पेश किया गया है उक्त आराजी के संबंध में एक इकरारनामा दिनांक 13.9.2023 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य निष्पादित किया गया था वादी द्वारा उक्त इकरारनामा की कोई पालना नहीं की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त इकरारनामा की पालना करवाने को तैयार व तत्पर है।

प्रतिवादी इकरारनामा दिनांक 13.09.2023 की पालना करने के लिए हमेशा तैयार व तत्पर रही परन्तु वादीगण शेष राशि देकर रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार नहीं थे और वादीगण शेष राशि देकर रजिस्ट्री करवाने को तैयार नहीं थे। और वादीगण प्रतिवादी को शेष राशि देने को तैयार नहीं थे। तथा प्रतिवादिया को नाजायज रूप से परेशान करने के लिए एक वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। अनुबंध पत्र की सुनवाई का एकमात्र क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है इसलिए वाद खारिज होने योग्य है।

वादीगण ने उक्त इकरारनामा की पालना के संबंध में सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार है। क्योंकि इकरारनामा की पालना केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही करवाई जा सकती है। वादी को इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में वाद पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादी का वाद विधि से बाधित होने से राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। इसलिए वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित होने से वाद खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज फरमाये जोन की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे बहस करना जाहिर किया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इकरारनामा दिनांक 13.09.2023 के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। उक्त भूमि रिकॉर्ड में प्रतिवादिया रिकॉर्डेड खातेदार है। जिसके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश नहीं किया जा सकता है। इकरारनामा के आधार पर दावा चलने योग्य नहीं है। सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक प्रफॉर्मिस एक्ट के तहत मुकदमा किया जावे। अतः दावा खारिज किया जावे। जबाब बहस में वकील वादी ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उठाई आपत्ति निराधार है तथा मैं इकरारनामों की पालना के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मुझे इकरारनामा की दिनांक से कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त कब्जे से बेदखल नहीं किया जावे इसलिए न्यायालय आया हूँ। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मुझे बेदखल नहीं करें। उक्त भूमि पर मेरा कब्जा काश्त है। प्रतिवादी उक्त भूमि अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर सकते हैं। इकरारनामा अभी लिमिटेशन में है उसमें लिखा है कि जब हमारा नाम हो जायेगी तो हम विक्रय पत्र तस्दीक करवा देंगे।

बहस तथ्यों पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 12(क) में इकरारनामा दिनांक 13.09.2023 के आधार पर प्रतिवादीगण को उक्त विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौकें की यथार्थिती बनाये रखने

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अनुतोष चाहा है। उक्त इकरारनामा की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। न्यायालय हाजा के लिए उक्त दावा क्षेत्राधिकार के बाहर होने से प्रकरण आदेश 07 नियम 11 सीपीसी से हिट होता है। अतः दावा क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण आदेश 07 नियम 11 के अनुसार बार्ड बाई लॉ है। फलस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा पेश अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी जाब्त दीवानी स्वीकार किया जाकर मौजूदा वाद वादी क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशिल कुमार सैनी)
सहायक क्लर्क एवं कार्यपालक
मैजिस्ट्रेट (फॉरस्ट्रिक) पाल्ना
मैजिस्ट्रेट (फॉरस्ट्रिक) पाल्ना